



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पुष्कर में “वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान” कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की स्टॉल्स का अवलोकन किया और महिलाओं को तुलसी के पौधे भी भेंट किए।

‘जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी, प्रदेश को “हरियालो राजस्थान” बनायेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल ने अजमेर में विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया, ब्रह्मा मंदिर में पूजा की

पुष्कर/जयपुर, 9 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल है तो कल है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण हम सबकी महती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जल की आवश्यकता को समझते हुए प्रदेशभर में विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने आ न किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े, जिससे राजस्थान में पानी की कमी नहीं रहे तथा हमारा प्रदेश हरियालो राजस्थान बने।

शर्मा सोमवार को पुष्कर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीर्थराज पुष्कर की इस पावन धरा पर पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहां स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री माता का मंदिर

■ **मुख्यमंत्री ने कहा, पुष्कर को धार्मिक व सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार पहले चरण में 127 करोड़ रुपये तथा दूसरे चरण में 38 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।**

विश्वभर में प्रसिद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए डेढ़ साल में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए लगातार निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए देशभर में ‘कैच द रेन’ अभियान प्रारंभ किया था। इस अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान का शुभारंभ किया।

शर्मा ने कहा कि पुष्कर को एक भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर एवं परिसर के विकास के

लिए विभिन्न कार्य चरणबद्ध रूप से करवाए जा रहे हैं। पहले चरण में लगभग 127 करोड़ रु. की लागत से घाट नवीनीकरण, सावित्री वाटिका, ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्मा घाट तक कॉरिडोर, ब्रह्मा चौक से वराह घाट तक कॉरिडोर सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। दूसरे चरण में कुल 38 करोड़ की लागत से नया मेला मैदान, प्रवेश और सूचना केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आमजन से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने

अजमेर जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत 13.51 करोड़ रुपये के 553 जल संग्रहण संरचनाओं तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत 9 करोड़ 61 लाख रुपये की 176 जल संग्रहण संरचनाओं का वचुंअली लोकार्पण किया। शर्मा ने अजमेर जिले के बंदिआ एवं मुहामी गांव के काँजवे एवं फीडर मरम्मत कार्य, फूल सागर भीर जलाशय का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा महिलाओं को तुलसी के पौधे भी भेंट किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तीर्थराज पुष्कर का पूजन तथा महालक्ष्मी द्वारा तैयार इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का पूजन किया। इसके अलावा, मंदिर परिसर में स्थित ब्रह्मा वाटिका में सिंदूर का पौधरोपण भी किया।

एसआई पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि उसके बेटे का जल्दी ही विवाह होने वाला है। इसके साथ ही उसकी नेटी का गौना भी होना है। इसलिए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि आरोपी जेल के अस्पताल से उचित चिकित्सा सुविधा हासिल कर रही है। ऐसे में केवल इस आधार पर उसे अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा, आरोपी श्रवण का बेटा नाबालिग है। इसलिए उसकी शादी भी संभव नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद, मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की है।

‘11 साल का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी लेने के लिए भी आमंत्रित किया। मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, “सुशासन और परिवर्तन पर स्पष्ट ध्यान। 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी के बल पर भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखे हैं। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत से प्रेरित होकर, एनडीए सरकार ने तेजी से और संवेदनशीलता के साथ युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक, जन-केन्द्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। हमें अपनी सामूहिक सफलता पर गर्व है, लेकिन साथ ही, हम एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आशा, विश्वास और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं।”

मेघालय के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनके पर्यटन पर असर पड़ता है। अब सरकार इस बात से राहत महसूस कर रही है कि यह मामला व्यक्तिगत था और “बो उत्तर भारतीयों” ही इसके लिए जिम्मेवार थे। जांच जारी है और जहाँ साजिशों की अनेक “कॉन्स्पिरेसी थ्योरी” चल रही हैं, तथ्य यह है कि यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है और हर जगह इसी की बात हो रही है!!

देश भर में करोना के 6491 एक्टिव केस

राहत की बात है कि गत 24 घंटों में करोना संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई

नयी दिल्ली, 09 जून। देशभर में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या सोमवार सुबह तक 6491 पहुंच गयी और राहत की बात यह है कि इसके संक्रमण से पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज सुबह आठ बजे तक 358 नए संक्रमण के मामले सामने आए, जिससे कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 6,491 हो गई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से संबंधित किसी अन्य मरीज की मौत नहीं हुई और मृतकों की संख्या 65 पर स्थिर है।

कोरोना संक्रमण के मामले में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां आज सुबह सक्रिय मामलों की संख्या 1957 तक पहुंच गई और दिल्ली में लगभग 42 नए मामले सामने आए, जिससे कुल

■ **करोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस (1957) केरल में हैं। राजस्थान में भी करोना पैर पसार रहा है, यहां 128 एक्टिव केस हैं।**

मामलों की संख्या 728 हो गई।

इसके अलावा गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747, महाराष्ट्र में 607, कर्नाटक में 423, तमिलनाडु में 219, उत्तर प्रदेश में 225, राजस्थान में 128, हरियाणा में 100, आंध्र प्रदेश में 85, पुदुचेरी में 11, सिक्किम में 31, मध्य प्रदेश में 43, झारखंड में चार, छत्तीसगढ़ में 41, बिहार में 50, ओडिशा में 34, जम्मू-कश्मीर में नौ, पंजाब में 35, असम में चार, गोवा में नौ, तेलंगाना में नौ, उत्तराखंड में छह, चंडीगढ़ में दो, हिमाचल प्रदेश तीन, त्रिपुरा में एक सक्रिय मामले हैं।

महागठबंधन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राहुल गांधी की जनसामान्य, खासतौर से उपेक्षित समुदायों एवं महिलाओं, तक पहुंच का गहरा असर हुआ है। हाल ही में हुई जातिगत जनगणना की घोषणा, जिसकी अधिसूचना 16 जून को की जायेगी, से जातिगत सक्रियता एवं लामबंदी में बहुत वृद्धि हुई है। बताया जाता है कि ओबीसी, एमबीसी तथा मुस्लिम वोट बैंक जदयू-भाजपा से दूर हो रहे हैं।

भाजपा की परेशानियों को बढ़ाने वाला एक बड़ा कारण यह भी है कि उसके पास कोई ऐसा प्रभावी स्थानीय नेता नहीं है, जो तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला कर सके। बिहार में भाजपा का कोई ऐसा नेता न होना, जो प्रचार को नेतृत्व दे सके तथा कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके, भाजपा की एक कमजोरी एवं कमी रही है। इसके अलावा, वक्फ के मुद्दे को विवाददायक तरीके से हैंडल

करने से बहुत से मुस्लिम मतदाता भाजपा से दूर हो गये हैं। वे अब आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के पीछे इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं।

राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर वर्तमान स्थिति बनी रहती है तो महागठबंधन दो-तिहाई सीटें हासिल कर सकता है। ठाकुर ने कहा, “बिहार में एनडीए की स्थिति तेजी से खराब हो रही है। अगर एनडीए अपने आंतरिक मतभेदों एवं टकरावों का समाधान नहीं करता है तथा नेतृत्व का कोई विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है, तो पटना जाने वाली सड़क उसके लिये ब्लॉक होती जा रही है।” बिहार की चुनावी लड़ाई जैसे-जैसे गति पकड़ रही है, सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि भाजपा अपनी रणनीति को कैसे सुधारती है या फिर एक नई शक्ति से परिपूर्ण विपक्षी मोर्चे द्वारा सत्ता से बाहर कर दिये जाने का खतरा उठाने की स्थिति में पहुंचती है।

मुंबई में लोकल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने दुर्घटना का मुख्य कारण अत्यधिक भीड़ बताया है, कथित तौर पर उस समय कोई यात्री ट्रेन के दरवाजों पर लटके हुए थे।

घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे अधिकारी और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच अभी चल रही है।

इस दुर्घटना से प्रभावित मार्ग पर लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गयी हैं। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि पांच लोगों की मौत हो गई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी लंबित है। बचाव और जांच के प्रयास जारी रहने के कारण आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रेलवे ने लोकल ट्रेन से गिरकर पांच ट्रेन यात्रियों की मौत की दुर्घटना मामले के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है।

सरकारी शिक्षक ने मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने का प्रयास किया

जनसुनवाई के दौरान यह शिक्षक मिठाई का डिब्बा व लिफाफे में पाँच हजार रुपये लेकर पहुँचा

जयपुर, 9 जून। शहर के सोडाला थाना इलाके के सिविल लाईंस स्थित एक सरकारी शिक्षक ने मंत्री के आवास पहुंचकर रिश्वत देने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। जानकारी में सामने आया कि आरोपित शिक्षक पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने के लिए जनसुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र लेकर आया था। इसके साथ एक लिफाफा और मिठाई का डिब्बा भी था। लिफाफे में पांच हजार रुपए थे। मामले की जानकारी मिलने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोडाला थाना पुलिस को सूचना दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, रुपयों का लिफाफा देने वाले युवक का नाम चंद्रकांत वैष्णव है और वह बाँसवाड़ा के घाटोल ब्लॉक में राजकीय उच्च

■ **बाँसवाड़ा के घाटोल ब्लॉक में कार्यरत चंद्रकांत वैष्णव को शिक्षा मंत्री की सूचना पर हिरासत में ले लिया गया।**

प्राथमिक विद्यालय बुधा में कार्यरत है। पुस्तक लेखन का काम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद करती है। उसी लेखन प्रक्रिया में आरोपित शिक्षक स्वयं को शामिल करवाना चाहता है। इसी मंशा के साथ सोमवार सुबह चंद्रकांत मंत्री के जयपुर में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि वे सोमवार सुबह जनसुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान, सरकारी शिक्षक

चंद्रकांत वैष्णव पाठ्यक्रम समिति में शामिल करने की मांग के लिए प्रार्थना पत्र लेकर आया। इसके साथ, शिक्षक एक लिफाफा और मिठाई का डिब्बा भी लाया था। लिफाफे में पांच हजार रुपए थे तो उन्होंने सामान्य लिफाफा समझ कर रख लिया, क्योंकि रोज सिफारिश के पत्र के साथ कई लिफाफे आते हैं। जब लिफाफा संदिग्ध दिखा तो उसे खोलने पर, उसमें पांच हजार रुपए थे। इस पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस अपने स्तर पर पूछताछ कर रही है तो वहीं, विभाग की एक अलग टीम भी जांच में जुटी है।

अरोपित टीचर एबीबीपी और संघ की विचारधारा से जुड़ा होना बताया गया है।

सरकारी शिक्षक ने पत्र में लिखा कि ‘वह छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीबीपी)

और संघ की विचारधारा से जुड़ा है। वह भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन से जुड़ा है तथा इसके अलावा, शिक्षा विभाग में विभागीय गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुका है। वर्तमान सरकार की मंशानुसार नई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति कक्षा 6-8 विज्ञान विषय में लेखक के रूप में शामिल करने की अनुशंसा करवाने का श्रम करे।

मंत्री दिलावर ने कहा कि यह मेरे जीवन की पहली घटना है। उनको लगभग 35 - 36 साल राजनीति में हो गए लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जब किसी को ये लगा हो कि शिक्षा मंत्री पैसे देकर काम करते हैं। पहले परंपराएं रही होंगी। इसलिए आरोपित शिक्षक ने हिम्मत की है। ये दुखद बात है कि लोगों की सोच ये है कि शिक्षा मंत्री पैसे लेते हैं।

पाक बमबारी में क्षतिग्रस्त घरों का अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा

नयी दिल्ली, 09 जून। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय से पाकिस्तान की गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए 2060 मकानों के लिए केंद्र सरकार के मुआवजे के अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करने को कहा है।

■ **केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए 2 लाख रु. और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए एक लाख रु. मुआवजा दिया जाएगा।**

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए हाल ही में मुआवजा राशि दिए जाने की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए दो लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि की घोषणा का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित कराया गया है।

ग्रैटा थनबर्ग के जहाज पर इज़रायल ने कब्जा किया

जानी मानी जलवायु एक्टिविस्ट ग्रैटा थनबर्ग 12 मानवाधिकारवादियों के साथ पानी के जहाज़ से गाज़ा पट्टी के लोगों के लिए सहायता ले जा रही थी

■ **इज़रायल की तमाम चेतावनियों के बाद भी जब “फ्रीडम फ्लोटिला” संगठन का जहाज मैडलीन नहीं रुका तो इज़रायल ने बीच समंदर में ही जहाज पर कब्जा कर लिया।**

■ **फ्रीडम फ्लोटिला की स्थापना गाज़ा के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए गई थी।**

तेल अवीव, 9 जून। फिलीस्तीन के गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ग्रैटा थनबर्ग (जानीमानी क्लाईमेट एक्टिविस्ट) सहित, 12 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के समूह के जहाज को इज़रायली सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसपर बीच समंदर इज़रायली सैनिक सवार हो गए हैं। इस जहाज का नाम मैडलीन है और फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन अभियान समूह ने टेलीग्राम ऐप पर कहा है कि जहाज से “कनैक्शन टूट गया है”। इसके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई जिसमें लाइफ जैकेट पहने लोग हाथ ऊपर करके बैठे दिख रहे हैं। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके एक्टिविस्ट्स ने दावा किया है कि उन्हें इज़रायली सेना ने किडनैप कर लिया है।

इज़रायल के रक्षा मंत्री इज़रायल काटज़ ने पहले ही अपनी सेना को आदेश दिया था कि जहाज को गाज़ा की नाकाबंदी तोड़ने से पहले ही रोक दिया जाए। इज़रायल का दावा है कि वह नहीं

1,218 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। वहीं, रविवार को, हमस द्वारा संचालित गाज़ा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाज़ा में मरने वालों की कुल संख्या 54,880 तक पहुंच गई है, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं। हमस के हमले से पहले से ही इज़रायल ने गाज़ा पर तौलैनिक नाकाबंदी लागू कर रखी है। यानी समुद्र के रास्ते वो गाज़ा में कुछ नहीं आने देता। इस नाकाबंदी का विरोध करने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए 2010 में फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन की स्थापना की गई थी।

शिक्षा मद के 2291 करोड़ रु. रोकने के मामले में तत्काल सुनवाई जरूरी नहीं

नयी दिल्ली, 09 जून। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार पर समग्र शिक्षा योजना (एसएसएस) की 2291.30 करोड़ रुपये की धनराशि रोकने का आरोप लगाते हुए उसका भुगतान करने का निर्देश देने की तमिलनाडु सरकार की याचिका पर शीघ्र तत्काल सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने मामले का विशेष उल्लेख करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन की तत्काल सुनवाई की दलीलें सुनने के बाद कहा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ग्रीष्मकालीन के बाद इस पर सुनवाई की जा सकती है।

तमिलनाडु सरकार ने लाखों बच्चों के पढ़ाई संबंधित नुकसान का हवाला देते हुए अपनी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। राज्य की द्रुपद सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर अपनी मूल याचिका में उसने केंद्र सरकार को 2,291.30 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें एक मई, 2025 से लेकर डिक्ली की प्राप्ति तक 2,151.59 करोड़ रुपये की मूल राशि पर छह फीसदी प्रति वर्ष ब्याज शामिल है।

“बाहरी” व्यक्तियों को खदेड़ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकारी और निजी संपत्ति को हुए कुछ नुकसान के साथ-साथ सड़कों पर हुई हिंसा के लिए वास्तव में इतनी कठोर कार्रवाई की जरूरत है। अधैसैनिक बलों की तैनाती, कथित रूप से डेमोक्रेसी पाटी के, लॉस एंजलिस के गवर्नर की इच्छा के विरुद्ध है।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, इस बीच इससे भी आगे बढ़ चुके हैं तथा उन्होंने और अधिक बल भेजने की बात कही है। उनके विदेश मंत्री, पीट हेगस्टेथ, ने चेतावनी दी है कि सक्रिय ड्यूटी वाले मरीन सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अशांत इलाकों में तैनाती के लिए सैनिक पेश किए तैयार हैं।

राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन और स्वयं राष्ट्रपति इस प्रदर्शन को एक अवसर के रूप में लेना चाहते हैं, ताकि वे घरेलू अशांति को दबाने के लिए सैनिकों की तैनाती की अपनी तत्परता दिखा सकें। अमेरिका में यह बात तुल्यता मानी जाती है कि एक

डैमोक्रेटिक व लिबरल सोसाइटी में किसी नागरिक विरोध को बल प्रयोग से दबाया जाए।

लेकिन ट्रंप के दो उद्देश्य हैं, पहला, अपने सख्त नेता की छवि को दर्शाना, और दूसरा, प्रशासन के लिए एक घटनाएं बहुत हानिकारक हैं, उनसे ध्यान हटाना, जैसे कि ट्रंप का तथाकथित “बिंग एंड ब्यूटीफुल बिल,” जिसका तात्पर्य है कि वे ‘खर्च और घाटे में वृद्धि के साथ-साथ अपने परम मित्र एनन मस्क के साथ खुले आम झगड़ा कर रहे हैं।

उदार विचारधारा वाले लोगों का मानना है कि यह एक ध्यान भटकाने की रणनीति है, जिसका खतरनाक सामाजिक प्रभाव हो सकता है। राष्ट्रपति जानबूझकर हिंसा और अशांति के दृश्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, ताकि अमेरिका की धरती पर नियमित सैनिकों की तैनाती के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। यहां तक कि पूर्व सैनिकों के कुछ संगठन भी, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विरोध प्रदर्शन को बढ़ाने

की ट्रंप की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं।

जिस तरह से देश अप्रवासियों और रंगभेद के खिलाफ कड़े रुख की ओर बढ़ रहा है, उसके कारण उच्च शिक्षा या नौकरी की तलाश के लिए अमेरिका एक खतरनाक जगह बनता जा रहा है। भारतीय छात्रों के साथ, जिनके वीजा बर्थे, गंभीर दुर्व्यवहार की खबरें भी सामने आई हैं।

विदेशी छात्रों में, चीनी छात्रों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है और कई के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, चीनी छात्रों के आवेदन में भारी गिरावट आई है। ये घटनाक्रम अमेरिका को बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। कई विदेशी छात्रों ने अमेरिका में काम करना जारी रखा है और देश के विकास में बहुत योगदान दिया है तथा दे रहे हैं। लेकिन डॉनल्ड ट्रंप और उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के बाद विदेशी प्रतिभाओं का प्रवाह अब बहुत कम हो जाएगा।